



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 230-2023/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, DECEMBER 30, 2023 (PAUSA 9, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

संख्या 71/एस0टी0-1.— चूंकि, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35) के अधीन बकाया देयों की वसूली समीचीन है, इसलिए, हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का 35) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, अधिनियम में निर्धारित अवधि के लिए निम्नलिखित स्कीम अर्थात् हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

1. (1) यह स्कीम हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारभ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

परिभाषाएं।

(क) “स्वीकृत कर” से अभिप्राय है, विवरणी में यथा स्वीकृत कर की कोई राशि, किन्तु जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है;

(ख) “आवेदक” से अभिप्राय है, कोई भी निर्धारिती या कोई व्यक्ति जो किसी बकाया देय का भुगतान करने के लिए दायी है, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, और जो इस स्कीम के अधीन शर्तों का अनुपालन करके इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है;

(ग) “नियत दिन” से अभिप्राय है, ऐसी तिथि जिसको इस स्कीम के उपबंध लागू होंगे;

(घ) “अंतरीय कर” से अभिप्राय है, सुसंगत अधिनियम के अधीन लागू कर की सम्पूर्ण दर और केन्द्रीय विक्री कर नियम, 1957 के नियम 12 के अधीन प्ररूप ‘ग’ और ‘च’ के रूप में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप प्रस्तुत करने पर लागू रियायती दर के बीच का अंतर:

परंतु जहां कर की रियायती दर का भुगतान विवरणी के साथ नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों को अंतरीय कर के अधीन कवर नहीं किया जाएगा और स्वीकृत, विवादित या निर्विवादित कर, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन कवर किया जाएगा;

- (ऽ) "विवादित कर" से अभिप्राय है, स्वीकृत कर, अंतरीय कर या निर्विवादित कर से अन्यथा कर की कोई राशि;
- (च) "निर्विवादित कर" से अभिप्राय है, स्वीकृत कर या अंतरीय कर से भिन्न कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित कोई कर की राशि, जिसमें सुसंगत अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी राशि के संबंध में नियत दिन को कोई अपील लंबित नहीं है;
- (छ) "आधिकारिक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, समुचित निर्धारण प्राधिकारी जिसकी आधिकारिता के अंतर्गत विशिष्ट आवेदक आता है;
- (ज) "सुसंगत अधिनियम" से अभिप्राय है, इस स्कीम के खंड 3 के उप-खण्ड (1) में यथा वर्णित अधिनियम;
- (झ) "व्यवस्थापन राशि" से अभिप्राय है, आवेदक द्वारा अपने बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।
- (2) इस स्कीम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाशित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सुसंगत अधिनियमों में दिए गए हैं।

स्कीम का
विस्तार और
लागूकरण।

3. (1) यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमों पर लागू होगी अर्थात्:-
- (i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6);
 - (ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74);
 - (iii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13);
 - (iv) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8);
 - (v) हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23);
 - (vi) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16);
 - (vii) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20)।
- (2) आवेदक किसी भी सुसंगत अधिनियम के अधीन स्कीम का चुनाव कर सकता है।
- (3) स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि सुसंगत अधिनियम के खजाना शीर्ष में जमा की जाएगी जिसके लिए स्कीम का चुनाव किया जा रहा है।

(4) आवेदक प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्ररूप ओटीएस-1 में अलग आवेदन करेगा, जिसके लिए वह अपने बकाया देयों का व्यवस्थापन करवाने का इरादा रखता है।

उदाहरण— श्रीमान एक्स को एक मांग प्राप्त हुई है जिसमें वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के लिए भी दायित्व शामिल हैं। इस मामले में, यदि श्रीमान एक्स अपने देयों का व्यवस्थापन करवाने का इच्छुक है, तो वह वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन अलग आवेदन करेगा। उसके दोनों आवेदनों को विशिष्ट माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

बकाया देयों का
व्यवस्थापन।

4. (1) इस स्कीम के अधीन बकाया देयों के व्यवस्थापन का विकल्प चुनने वाले किसी आवेदक को, उसके बकाया देयों के बदले में, व्यवस्थापन द्वारा, अनुसूची-I में यथा वर्णित राशि का भुगतान करना होगा।

(2) आवेदक अपनी बकाया देयों के व्यवस्थापन के लिए अनुसूची-II में उपलब्ध विकल्प के अनुसार एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है।

(3) आवेदक विलंब की अवधि के लिए अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष अतिरिक्त ब्याज के भुगतान के साथ तीसरी किस्त की अंतिम तिथि तक दूसरी किस्त का भुगतान कर सकता है।

(4) यदि अनुसूची-II में निर्दिष्ट अवधि, या उपरोक्त उप-खण्ड (3) में निर्दिष्ट अवधि, के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो स्वीकृति का अनंतिम आदेश वापस ले लिया गया समझा जाएगा और यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और आवेदक के विरुद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाएगी और अधिकारिता प्राधिकारी तदनुसार प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा।

5. (1) आवेदक नियत दिन से नब्बे दिन के भीतर स्कीम का विकल्प चुन सकता है।
 (2) आवेदक व्यवस्थापन राशि या प्रथम किस्त, जो भी लागू हो, के भुगतान के प्रमाण के साथ प्ररूप ओटीएस-1 में ॉनलाइन आवेदन करेगा।
 (3) प्ररूप ओटीएस-1 प्राप्त होने पर, आवेदक को प्ररूप ओटीएस-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिस्टम जनित पावती जारी की जाएगी।
6. आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्—
 (क) आधिकारिक प्राधिकारी पावती की तिथि से तीस दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस-1 की जांच करेगा और संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (जिसे, इसमें, इसके बाद "डीईटीसी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को अपनी टिप्पणियों सहित सिफारिश के लिए आवेदन भेजेगा;
 (ख) यदि किसी आधिकारिक प्राधिकारी के पास विश्वास करने के कारण हैं कि कोई विशिष्ट आवेदन उसके वार्ड से सम्बन्धित नहीं है, तो वह ऐसे आवेदन को डीईटीसी को अंतरित कर सकता है। तब डीईटीसी ऐसे आवेदन को सम्बन्धित आधिकारिक प्राधिकारी को आवेदन के प्रसंस्करण के लिए अंतरित करेगा। ऐसे सामलों में, उपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा आवेदन के ऐसे अंतरण की तिथि से होगी;
 (ग) डीईटीसी पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन की जांच करेगा और आधिकारिक प्राधिकारी को या तो प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस या प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश (जहां आवेदक ने किश्तों का चुनाव किया है या अपील वापस लेने का सबूत करना अपेक्षित है) या प्ररूप ओटीएस 4 में अंतिम व्यवस्थापन आदेश जारी करने के लिए सामले को वापस भेजेगा;
 (घ) डीईटीसी से संसूचना प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस या प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा;
 (ड) आवेदक प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता का नोटिस जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर अपेक्षित दस्तावेजों या यथा अपेक्षित भुगतान के प्रमाण के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप ओटीएस 3क में अपना जवाब प्रस्तुत करेगा;
 (च) आवेदक से प्ररूप ओटीएस 3क में जवाब प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी सामले की जांच करेगा और प्ररूप ओटीएस 3क प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश के साथ उसे डीईटीसी को भेजेगा। डीईटीसी पन्द्रह दिन के भीतर और आधिकारिक प्राधिकारी को या तो प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस-5 में अस्वीकृति का आदेश जारी करने का निर्देश देगा;
 (छ) डीईटीसी द्वारा जारी निर्देश प्राप्त होने पर, आधिकारिक प्राधिकारी ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर सामले की जांच करेगा और आधिकारिक प्राधिकारी को या तो प्ररूप ओटीएस 4क में अनंतिम व्यवस्थापन आदेश या प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस 5 में अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा;
 (ज) स्कीम का चयन करने में रुचि रखने वाले किसी भी आवेदक को सुसंगत अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी, किसी वैधानिक आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, को पूर्ण रूप में और बिना शर्त के वापिस लेना होगा और प्ररूप ओटीएस 4क की प्राप्ति से एक सौ अस्सी दिन के भीतर व्यवस्थापन के अंतिम आदेश से पूर्व ऐसी अपील को वापिस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस 6 में आधिकारिक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा;
 (झ) यदि प्ररूप ओटीएस 4क की प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्ररूप ओटीएस 6 प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आवेदक ने आवेदन नहीं किया था और आवेदक के विरुद्ध लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन लंबित कार्यवाही जारी रहेगी;
 (झ) उन आवेदकों के लिए, जिन्होंने इस स्कीम का चुनाव किया है, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों को तब तक प्रास्थागित रखा जाएगा, जब तक इस स्कीम के अधीन प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश या प्ररूप ओटीएस 5 में रद्दकरण का आदेश पारित नहीं किया जाता है;

आवेदन की प्रक्रिया।

प्ररूप का सत्यापन तथा समय सीमा का विस्तार।

- (ट) जहां प्ररूप ओटीएस 5 में व्यवस्थापन के रद्दकरण का आदेश जारी किया जाता है, आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, सुसंगत अधिनियम के अधीन उसकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी और किसी भी मामले में ऐसी राशि का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।
- 7.** (1) ऐसे आवेदक भी स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके बकाया देयों को आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन ऐसे देयों की वसूली के लिए हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया है।
- (2) आधिकारिक प्राधिकारी, प्ररूप ओटीएस 4 के सफलतापूर्वक जारी होने के बाद, प्ररूप जीएसटी डीआरसी 07क के माध्यम से सृजित मांग को संशोधित करेगा और हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 का प्ररूप जीएसटी डीआरसी 08क जारी करेगा।
- 8.** (1) स्कीम के अधीन भुगतानयोग्य राशि के संबंध में पारित व्यवस्थापन का अंतिम आदेश, इसमें कथित मामले और समय अवधि के संबंध में निर्णयक होगा और आवेदक,—
- (क) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश में सम्मिलित मामले और समय अवधि के संबंध में कोई अतिरिक्त कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा;
- (ख) आदेश में सम्मिलित मामले और समय अवधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन अभियोजित किए जाने का दायी नहीं होगा।
- (2) ऐसे आदेश में सम्मिलित सभी मामले और समय अवधि को सुसंगत अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर नए सिरे से विचार नहीं किया जाएगा:
- परंतु यदि जहां आवेदन में दिए गए किसी तात्त्विक विवरण, व्यवस्थापन के आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर बाद मिथ्या पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि आवेदन कभी नहीं किया गया था और लागू सुसंगत अधिनियम के अधीन आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाएगी।
- 9.** नियत दिन से पूर्व भुगतानयोग्य या भुगतान किए गए कर, ब्याज या शास्ति की राशि या किसी अन्य धनराशि का इस स्कीम के अधीन प्रदाय नहीं किया जाएगा या समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 10.** प्राधिकारी, जिसने इस स्कीम के अधीन अंतिम आदेश पारित किया है, ऐसी किसी त्रुटि का सुधार कर सकता है, जो ऐसे आदेश के अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो, या तो स्वप्रेरणा से या जहां ऐसी त्रुटि ऐसे आदेश को जारी करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रभावित व्यक्ति द्वारा ऐसी त्रुटि उसके संज्ञान में लाई जाती है।
- 11.** यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबन्धों से अनअसंगत प्ररूपों में संशोधन सहित ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
- 12.** इस स्कीम से उत्पन्न किसी संदेह के मामले में, उस पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.** निम्नलिखित आवेदक इस स्कीम का चुनाव करने के पात्र नहीं होंगे, यदि—
- (क) सुसंगत अधिनियमों के अधीन किसी भी कारण से आवेदक के विरुद्ध दाखिल कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं;
- (ख) सुसंगत अधिनियम के अधीन त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित मांग।
- 14.** इस स्कीम के अधीन भुगतान की गई कोई भी राशि न तो इनपुट कर के माध्यम से भुगतान की जाएगी और न ही सुसंगत अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा इनपुट कर के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 15.** इस स्कीम के अधीन आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा पारित व्यवस्थापन के अंतिम आदेश के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं हो सकेगी।

16. (1) सरकार या तो अपनी स्वप्रेरणा से या हितधारकों के प्रतिवेदन पर इस स्कीम के अधीन आवेदन करने के लिए समय अवधि में विस्तार कर सकती है। समय अवधि में विस्तार।

(2) संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) मामले दर मामले के आधार पर डीईटीसी या आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस या आदेश या किसी सिफारिश को जारी करने की समय अवधि में अभिलिखित कारणों से तीस दिन से अनधिक की अवधि का विस्तार कर सकता है।

17. (1) इस स्कीम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। क्षतिपूर्ति।

(2) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध केवल आवेदक द्वारा भुगतानयोग्य बकाया देयों की राशि की गणना में बाद में त्रुटि का पता चलने के आधार पर तब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी जब तक कदाचार का सबूत न हो।

अनुसूची—I : बकाया देय के बदले में भुगतान की जाने वाली व्यवस्थापन राशि

[दोखिए खण्ड 4 (1)]

1.	2.	3.	4.	5.
क्रम संख्या	प्रवर्ग	भुगतानयोग्य कर या किसी अन्य राशि की प्रतिशतता।	खाना 3 के अनुसार भुगतानयोग्य कर या किसी अन्य राशि से सम्बन्धित व्याज की प्रतिशतता	खाना 3 के अनुसार भुगतानयोग्य कर या किसी अन्य राशि से सम्बन्धित शास्ति की प्रतिशतता
1.	स्वीकृत कर	100 प्रतिशत	शून्य प्रतिशत	शून्य प्रतिशत
2.	विवादित कर	<ul style="list-style-type: none"> • 50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम कर राशि के मामले में 30 प्रतिशत • अन्य सभी मामलों में 50 प्रतिशत 	शून्य प्रतिशत	शून्य प्रतिशत
3.	निर्विवादित कर	<ul style="list-style-type: none"> • 50 लाख रुपये से कम या उसके बराबर कर राशि के मामले में 40 प्रतिशत • अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत 	शून्य प्रतिशत	शून्य प्रतिशत
4.	अंतरीय कर	30 प्रतिशत	शून्य प्रतिशत	शून्य प्रतिशत

अनुसूची-II : किस्तों में भुगतान करने का विकल्प

[दैखिए खण्ड 4 (2)]

1.	2.	3.	4.	5.
क्रम संख्या	कर की व्यवस्थापन राशि (अनुसूची-I के खाना 3 में निर्दिष्ट) (रुपये में)	आवेदन के समय भुगतान की जाने वाली राशि	दूसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर)	तीसरी किस्त (व्यवस्थापन के अनंतिम आदेश की तिथि से 180 दिन के भीतर)
1.	10 लाख तक	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ भुगतान की जाने वाली पूर्ण तथा अंतिम व्यवस्थापन राशि।	शून्य	शून्य
2.	10 लाख से 25 लाख तक	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 50 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत।	शून्य
3.	25 लाख से ज्यादा	प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 40 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का 30 प्रतिशत।	प्ररूप ओटीएस-1ख में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 30 प्रतिशत।

प्ररूप ओटीएस -1
[देखिए खण्ड 3, 5 और 6]

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 चुनने के लिए आवेदन प्ररूप

<<सिस्टम द्वारा उत्पन्न अद्वितीय संख्या और दिनांक>>

क्रम संख्या		विवरण
1	(क)	आवेदक का नाम (कृपया आवेदक की परिभाषा दें)
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया अपंजीकृत का उल्लेख करें)
	(ग)	स्थायी खाता संख्या
	(घ)	मोबाइल
	(ङ)	ईमेल आईडी
	(च)	एससीओ/बूथ/दुकान/बिल्डिंग/फ्लैट/फ्लोर संख्या
	(छ)	सेक्टर/क्षेत्र
	(ज)	शहर/ कस्बा /गाँव
	(झ)	जिला
	(ञ)	पिन कोड
2	(क)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम ***
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर
	(घ)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी आईडी प्रमाण (पैन/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/पीपीपी या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी कार्ड)
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।	सुसंगत अधिनियम <<द्रौप डाउन>> निर्धारण वर्ष <<द्रौप डाउनज़ा>> (केवल एक ही विकल्प चुना जा सकता है)
4	क्या सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है?	हाँ <input checked="" type="checkbox"/> यदि हाँ चुना गया है तो निम्नलिखित टिप्पणी बॉक्स खुल जाना चाहिए: 1. केस संख्या <input type="text"/> 2. प्राधिकरण के समक्ष लंबित <input type="text"/> 3. अपील दायर करने की तिथि <input type="text"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/> << अनिवार्य क्षेत्र >>
5	क्या आवेदक के खिलाफ सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी कारण से आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है?	हाँ <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/> << यदि हाँ चयनित है, तो ओटीएस 1 उत्पन्न नहीं किया जा सकता >>
6	क्या मांग सुसंगत अधिनियम के अधीन गलत प्रतिदाय से संबंधित है?	हाँ <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/> << यदि हाँ चयनित है, तो ओटीएस 1 उत्पन्न नहीं किया जा सकता >>

7 अनुसूची-I के अनुसार बकाया देयों के व्यवस्थापन का विवरण,-													
क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड >>	निर्धारण वर्ष << ऑटो पॉपुलेटेड >>	आदेश संख्या जिसके माध्यम से बकाया देय निर्धारित किया गया << अनिवार्य >>	आदेश की तिथि << अनिवार्य >>	खाना संख्या (4) में कथित आदेश में अन्तर्वर्लित कुल राशि << अनिवार्य >>	चुनिए 1.स्थीरूत कर 2.विवादित कर 3.अविवादित कर 4.अंतरीय कर << ड्रॉप डाउन >> (अनेक विकल्प) << अनिवार्य >>	खाना संख्या (7) में भुगतान योग्य में खाना 3 अनुसूची I अंतर्वर्लित के अनुसार व्यवस्थापन योग्य (ऑटो पॉपुलेटेड)	खाना संख्या (8) के बदले अनुसूची I अनिवार्य << अनिवार्य >>	शामिल व्याज की कुल राशि << अनिवार्य >>	खाना संख्या (10) के बदले अनुसूची I में खाना 4 के अनुसार व्यवस्थापन राशि (ऑटो पॉपुलेटेड)	अन्तर्वर्लित शास्ति की कुल राशि << अनिवार्य >>	खाना संख्या (12) के बदले अनुसूची I के खाना 5 के अनुसार व्यवस्थापन राशि (ऑटो पॉपुलेटेड)	शुद्ध भुगतानयोग्य राशि (9+11+13) << अनिवार्य >>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
जोड़													
8	7(14) के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि										ऑटो पॉपुलेटेड, 7(14) के कुल आंकड़े		
9	7(9) के अनुसार देय के व्यवस्थापन का प्रवर्ग										<10 लाख, 10-25 लाख, >25 लाख << ऑटो पॉपुलेटेड >>		
10	क्या किस्त सुविधा का विकल्प चुना गया है?										हाँ <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	लागू नहीं <input type="checkbox"/> (यदि क्रम संख्या 9 में देय 10 लाख से कम है)	
11	किस्त अनुसूची										तीसरी किस्त की राशि	तीसरी किस्त की तिथि	
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि	प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
1													
12	किए गए भुगतान का विवरण—										सीआईएन की तिथि	राशि(रुपये में)	
	क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
	1												
	2												
	<input type="checkbox"/> में सहमत हूँ कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।										Total		
13	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज										1. रथाई खाता संख्या 2. निर्धारण आदेश जिसके द्वारा देय निर्धारित किया गया था 3. लंबित अपीलों का प्रमाण, यदि कोई हो 4. भुगतान का प्रमाण 5. कोई अन्य दस्तावेज		

14	<p>घोषणा:</p> <p>मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि ऊपर कथित सूचना और घोषणाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 को इसके निबंधनों और शर्तों को पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना गया है।</p> <p>मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं, मुझे यथा लागू व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।</p> <p style="text-align: right;">(आवेदक का नाम) << स्व – जनित >> (संपादन योग्य)</p> <p>स्थान: _____ दिनांक: << स्व – जनित >></p> <p>टिप्पणि:— सभी राशियां रुपये में भुगतान की जाएं।</p>
----	---

**

व्यवसाय की रचना	वह व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकता है
स्वामित्व	मालिक
साझेदारी	प्रबंध / प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभाजित परिवार	कर्ता
प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
सीमित लोक समवाय	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
सोसायटी / क्लब / ट्रस्ट / एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक
सीमित देयता भागीदारी	नामित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
सांविधिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित देयता भागीदारी	भारत में अधिकृत व्यक्ति
अन्य (निर्दिष्ट करें)	प्रभारी व्यक्ति

प्ररूप ओटीएस-1(क)

[देखिए अनुसूची II]

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन दूसरी किस्त की सूचना
 <<सिस्टम द्वारा उत्पन्न विशिष्ट संख्या और तिथि>>

क्रम संख्या	विवरण							
1	(क)	आवेदक का नाम						
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया 'अपंजीकृत' का उल्लेख करें)						
	(ग)	ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि						
	(घ)	ओटीएस-4क की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि						
	(ङ)	आधिकारिक जिला						
	(च)	आधिकारिक वार्ड						
2	(क)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम						
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी						
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल संख्या						
3	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है							
4	प्ररूप ओटीएस 1 की क्रम संख्या 8 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि							
5	प्ररूप ओटीएस 4क के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि							
6	किस्त अनुसूची स्कीम << प्ररूप ओटीएस 4क से ऑटो पॉपुलेटेड >>							
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि	प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि	तीसरी किस्त की तिथि
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1							
	7	उपरोक्त 6(5) के अनुसार भुगतान की जाने वाली किस्त की राशि						
	8	किस्त के विलंबित भुगतान पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, यदि कोई हो						
	9	किए गए भुगतान का विवरण—						
	क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	1							
	2							
	□ मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।					कुल		

10	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज
11	<p style="text-align: center;">घोषणा:</p> <p>मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि ऊपर कथित सूचना और घोषणाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 को इसके निबंधनों और शर्तों को पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना गया है।</p> <p>मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं, मुझे यथा लागू व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।</p> <p style="text-align: right;">(आवेदक का नाम) << स्व – जनित >> (संपादन योग्य)</p> <p>स्थान: _____ दिनांक: << स्व – जनित >></p> <p>टिप्पणः—सभी राशियां रूपये में भुगतान की जाएं।</p>	

प्ररूप ओटीएस-1(ख)

[देखिए अनुसूची II]

हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन तीसरी किस्त की सूचना

<<सिस्टम द्वारा उत्पन्न विशिष्ट संख्या और तिथि>>

क्रम संख्या	विवरण										
1.	(क)	आवेदक का नाम									
	(ख)	सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या (यदि पंजीकृत है) (यदि पंजीकृत नहीं है तो कृपया 'अपंजीकृत' का उल्लेख करें)									
	(ग)	प्ररूप ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि									
	(घ)	प्ररूप ओटीएस-1 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि									
	(ङ)	प्ररूप ओटीएस-4 की सिस्टम जनित विशिष्ट संख्या और तिथि									
	(च)	आधिकारिक जिला									
	(छ)	आधिकारिक वार्ड									
2.	(क)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम									
	(ख)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी									
	(ग)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या									
3.	सुसंगत अधिनियम का नाम और अवधि जिसके लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।										
4.	प्ररूप ओटीएस-1 की क्रम संख्या 8 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि										
5.	प्ररूप ओटीएस 4 के अनुसार कुल व्यवस्थापन राशि										
6.	किस्त अनुसूची << प्ररूप ओटीएस 4 क से आँटो पॉपुलेटेड >>										
	क्रम संख्या	कुल व्यवस्थापन राशि	प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि					
	1	2	3	4	5	6					
						7					
						8					
7.	उपरोक्त 6(7) के अनुसार भुगतान की जाने वाली किस्त की राशि										
8.	किए गए भुगतान का विवरण—										
	क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन		सीआईएन की तिथि					
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					
	1										
	2										
	मैं सहमत हूं कि ऊपर दिए गए जीआरएन विवरण की जांच कर ली गई है और पहले कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया गया है।										
9.	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज										
10.	घोषणा:										
	मैं यहां यह घोषणा करता हूं कि ऊपर कथित सूचना और घोषणाएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और कि इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 को इसके निंबधनों और शर्तों को पूर्ण रूप से समझने के बाद चुना गया है।										
मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं, मुझे यथा लागू व्यवस्थापन राशि का भुगतान करूंगा। मैं आगे पुष्टि करता हूं कि किसी भी लंबित राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में, स्कीम के अधीन किए गए किसी भी भुगतान को सुसंगत अधिनियम के अधीन मेरी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।											
(आवेदक का नाम)											
स्थान: _____											
दिनांक: << स्व - जनित >> (संपादन योग्य)											

टिप्पणी:—सभी राशियां रूपये में भुगतान की जाएं।

प्ररूप ओटीएस-2*[देखिए खण्ड 5 (3)]***प्ररूप ओटीएस-1 में आवेदन की पावती**

इसके द्वारा, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन _____ (सुसंगत अधिनियम का नाम) से सम्बन्धित बकाया देयों के व्यवस्थापन हेतु निर्धारण वर्ष _____ के लिए प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन, संदर्भ संख्या _____ दिनांक _____ स्वीकार किया जाता है।

आबकारी तथा कराधान विभाग
हरियाणा सरकार

“यह एक सिस्टम जनित पावती है और इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है”

प्ररूप ओटीएस-3
[देखिए खण्ड 6]
अपूर्णता सूचना (नोटिस)

सेवा में

आवेदक का नाम << ऑटो पॉपुलेटेड >>
 आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड >>
 टिन/आरसी नंबर (यदि लागू हो) <<ऑटो पॉपुलेटेड>>
 ओटीएस 3 संदर्भ संख्या <<सिस्टम जनित>> दिनांक <<सिस्टम जनित>>

विषय:- अपूर्णता सूचना (नोटिस)।

संदर्भ:- प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के अधीन आवेदन किया है। आपके आवेदन, संदर्भ संख्या _____ दिनांक _____ की जांच करने पर, प्ररूप ओटीएस-1 में निम्नलिखित अपूर्णताएं देखी गई हैं:

- (i)
- (ii)
- (iii)

<<अपलोड विकल्प>>

इस सूचना (नोटिस) पर आपका उत्तर इस सूचना (नोटिस) की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान के प्रमाण (यदि कोई हो) सहित प्ररूप ओटीएस-3क में अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जाना चाहिए। इस सूचना (नोटिस) की शर्तों का पालन करने में विफलता की दशा में, आपका आवेदन आगे कोई सूचना (नोटिस) दिए बिना खारिज कर दिया जाएगा और स्कीम के अधीन किया गया भुगतान सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और किसी भी दशा में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी

जिला _____

वार्ड _____

प्ररूप ओटीएस 3क

[देखिए खण्ड 6]

अपूर्णता सूचना (नोटिस) का उत्तर

सेवा मे,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला <<झौंप डाउन>>

वार्ड <<झौंप डाउन>>

आवेदक का नाम <<ऑटो पॉपुलेटेड >>

आवेदक का पता <<ऑटो पॉपुलेटेड >>

प्ररूप ओटीएस 3 सूचना (नोटिस) संख्या का विवरण <<ऑटो पॉपुलेटेड >> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड >>

टिन/आर सी नंबर. (यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड >>

विषय:- प्ररूप ओटीएस 3 में अपूर्णता सूचना (नोटिस) का उत्तर।

संदर्भ:- प्ररूप ओटीएस 3 संदर्भ संख्या.<<ऑटो पॉपुलेटेड >> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड >>

यह प्ररूप ओटीएस 3 में आपके कार्यालय से जारी अपूर्णता सूचना (नोटिस) संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड >> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड >> के संदर्भ में हैं उठाई गई अपूर्णता का बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार है:

(क)

(ख)

(ग)

किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जीआरएन की क्रम संख्या	जीआरएन की तिथि	सीआईएन की क्रम संख्या	सीआईएन की तिथि	राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
जोड़					
अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज					1. भुगतान का प्रमाण 2. कोई अन्य दस्तावेज

(आवेदक का नाम)

<< स्व - जनित >> (संपादन योग्य)

स्थान: _____

दिनांक: << स्व - जनित >>

टिप्पणी:- सभी राशियां रुपये में भुगतान की जाएं।

प्ररूप ओटीएस-4क

[देखिए खण्ड 6]

सेवा मे,

आवेदक का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड >>

आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड >>

टिन/आर सी नंबर.(यदि लागू हो) << ऑटो पॉपुलेटेड >>

आदेश संख्या <<सिस्टम जनित>> दिनांक <<सिस्टम जनित>>

विषय: - व्यवस्थापन का अनंतिम आदेश।

संदर्भः - प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 का विकल्प चुना है। जांच करने पर, आपका आवेदन सही पाया गया है। तदनुसार, अनंतिम व्यवस्थापन का आदेश निम्नानुसार पारित किया जाता है:

सुसंगत अधिनियम का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

निर्धारण वर्ष << ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

तालिका -I

तालिका -II

किस्त अनुसूची <<ऑटो पॉपुलेटेड लेकिन संपादन योग्य>>							
क्रम संख्या.	कुल व्यवस्थापन राशि	प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त की तिथि	दूसरी किस्त की राशि	दूसरी किस्त की तिथि	तीसरी किस्त की राशि	तीसरी किस्त की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i)							

तालिका -III

क्रम संख्या	विवरण	राशि (Rs.)
i.	तालिका-I के अनुसार भुगतानयोग्य व्यवस्थापन राशि	
ii.	कमी: आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि	
iii.	शेष (1-2)	

यह एक अनंतिम आदेश है तथा पूर्ण भुगतान करने और आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस 6 में लंबित अपीलों को वापस लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने, यदि लागू हो, के पश्चात् प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____

प्ररूप ओटीएस-4

[देखिए खण्ड 6 और 7]
व्यवस्थापन का अंतिम आदेश

सेवा मे,

आवेदक का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता << ऑटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर.(यदि लागू हा)<< ऑटो पॉपुलेटेड>>

आदेश संख्या<< सिस्टम जनित >> दिनांक << सिस्टम जनित >>

विषय: - व्यवस्थापन का अंतिम आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या<< ऑटो पॉपुलेटेड>> दिनांक << ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की विस्तार से जांच की गई है, तदनुसार व्यवस्थापन का अंतिम आदेश निम्नानुसार पारित किया गया है:

सुसंगत अधिनियम का नाम<< ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>> निर्धारण वर्ष<< ऑटो पॉपुलेटेड/ संपादन योग्य>>

तालिका -I

क्रम संख्या	विवरण	राशि (Rs.)
1.	प्ररूप ओटीएस-1 / ओटीएस-4क के अनुसार भुगतायोग्य व्यवस्थापन राशि	
2.	कमी: - क. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस 1 में भुगतान की गई राशि (प्रथम किस्त) ख. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस 1 (क) में भुगतान की गई राशि की सूचना (दूसरी किस्त)* ग. आवेदक द्वारा प्ररूप ओटीएस 1 (ख) में भुगतान की गई राशि की सूचना (तीसरी किस्त)	
3.	दूसरी किस्त में विलम्बित भुगतान के बदले में ब्याज का भुगतान	
4.	शेष (1-2)	<< यह शून्य होना चाहिए >>

* विलम्बित किस्त पर ब्याज, यदि कोई हो, का उल्लेख इस खाने में नहीं किया जाएगा।

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी भी अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील, यदि कोई हो, वापस ले ली गई है और ऐसी अपील वापस लेने का प्रमाण प्ररूप ओटीएस-6 में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी क्रम संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ऑटो पॉपुलेटेड>> अंकित है।

आपके आवेदन, किए गए भुगतान और विचाराधीन सभी अन्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत, मुझे पता चला है कि आपके निम्नलिखित बकाया देय का, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 के माध्यम से व्यवस्थापन किया गया है।

तालिका-II

क्रम संख्या	सुसंगत अधिनियम	निर्धारण वर्ष	व्यवस्थापन राशि
क्र.	ख.	ग.	घ.
1.			
2.			
जोड़			

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____

प्ररूप ओटीएस-5

[देखिए खण्ड 4]
रद्दकरण का आदेश

सेवा मे,

आवेदक का नाम<<ऑटो पॉपुलेटेड>>
आवेदक का पता<<ऑटो पॉपुलेटेड>>
टिन/आर सी नंबर.(यदि लागू हो)<<ऑटो पॉपुलेटेड>>
आदेश संख्या<< सिस्टम जनित >> दिनांक <<सिस्टम जनित>>

विषय: - रद्दकरण का आदेश।

संदर्भ: - प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>
प्ररूप ओटीएस-3 संख्या, यदि लागू हो<<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>>

चूंकि, आपने संदर्भ संख्या <<ऑटो पॉपुलेटेड>>दिनांक<<ऑटो पॉपुलेटेड>> वाले प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम, 2023 का विकल्प चुना है। आपके आवेदन की जांच की गई और उसे सही नहीं पाया गया और प्ररूप ओटीएस 1 मे आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण दर्ज किए गए हैं: -

- (क)
- (ख)
- (ग)

<< अपलोड विकल्प >>

आपको, यह सूचित किया जाता है कि स्कीम के अधीन भुगतान की गई राशि सुसंगत अधिनियम के अधीन आपकी देयताओं के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी
जिला _____
वार्ड _____

प्ररूप ओटीएस 6

[देखिए खण्ड 6]

सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेने के संबंध में सूचना

<< सिस्टम जनित संदर्भ संख्या >>

सेवा मे,

आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

जिला < झूँप डाउन >

वार्ड < झूँप डाउन >

आवेदक का नाम <<ओटो पॉपुलेटेड>>

आवेदक का पता <<ओटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या का विवरण <<ओटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ओटो पॉपुलेटेड>>

टिन/आर सी नंबर (यदि लागू हो) <<ओटो पॉपुलेटेड>>

विषय: - सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपील को वापस लेना ।

संदर्भ – प्ररूप ओटीएस 1 संदर्भ संख्या <<ओटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ओटो पॉपुलेटेड>>

प्ररूप ओटीएस-1 संदर्भ संख्या <<ओटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ओटो पॉपुलेटेड>> में मेरी घोषणा और प्ररूप ओटीएस 4क में आपके आदेश <<ओटो पॉपुलेटेड>> दिनांक <<ओटो पॉपुलेटेड>> के अनुपालन में, मैंने (आवेदक का नाम) _____ सुसंगत अधिनियम <<ओटो पॉपुलेटेड>> के अधीन निर्धारण वर्ष <<ओटो पॉपुलेटेड>> के लिए <<ओटो पॉपुलेटेड>> (प्राधिकरण का नाम उल्लेखित करें) के समक्ष निर्धारण आदेश के विरुद्ध लंबित अपील वापस ले ली है। ऐसी वापसी का प्रमाण इसके साथ संलग्न है।

<< अपलोड विकल्प >>

मैं समझता हूं कि प्ररूप ओटीएस 4 में व्यवस्थापन का अंतिम आदेश आधिकारिक प्राधिकारी द्वारा वापसी के ऐसे प्रमाण को स्वीकार करने पर ही पारित किया जाएगा।

(आवेदक का नाम)

स्थान: _____

<< स्व – जनित >> (संपादन योग्य)

दिनांक: << स्व – जनित >>

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th December, 2023

No. 71/ST-1.— Whereas, it is expedient for the recovery of outstanding dues under the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017, therefore, in exercise of powers conferred under section 3 of the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (35 of 2017), the Governor of Haryana hereby notifies the following scheme namely **The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023**, for the period as prescribed in the Act, subject to the following conditions and restrictions, namely:-

1. (1) This scheme may be called '**The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023**'.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. For the purposes of this scheme, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

(a) "**admitted tax**" means any amount of tax as admitted in return but not paid or short paid;

(b) "**applicant**" means any assesee or any person who is liable to pay any outstanding dues, whether registered or not, and who desires to avail the benefit of the scheme by complying with the conditions under this scheme;

(c) "**appointed day**" means the date on which the provisions of this scheme shall come into force;

(d) "**differential tax**" means the difference between the full rate of tax applicable under the relevant Act and the concessional rate applicable on submission of declaration forms as specified as Form 'C' and 'F' under rule 12 of the Central Sales Tax Rules, 1957:

Provided that where the concessional rate of tax has not been paid alongwith the return, then such cases shall not be covered under differential tax and shall be covered under the admitted, disputed or undisputed tax, as the case may be;

(e) "**disputed tax**" means any amount of tax other than admitted tax, differential tax or undisputed tax;

(f) "**undisputed tax**" means any amount of tax, other than the admitted tax or differential tax, as quantified by the taxing authority wherein no appeal is pending on the appointed day in relation to such amount before the appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court;

(g) "**jurisdictional authority**" means the appropriate assessing authority under whose jurisdiction the particular applicant falls;

(h) "**relevant Act**" means the Acts as mentioned in clause 3(1) of this scheme;

(i) "**settlement amount**" means the amount to be paid by the applicant for the settlement of his outstanding dues;

(2) Words and expressions used in this scheme, but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the relevant Act.

3. (1) The scheme shall be applicable to the following Acts, namely :-

Scope and application of the scheme.

(i) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);

(ii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956) ;

(iii) The Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (13 of 2000);

(iv) The Haryana Tax on Entry of Goods in to Local Areas Act, 2008 (8 of 2008) ;

(v) The Haryana Tax on Luxuries Act, 2007 (23 of 2007) ;

(vi) The Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955) ;

(vii) The Haryana General Sales Tax Act, 1973 (20 of 1973)

(2) An applicant may opt for the Scheme under any of the relevant Act.

(3) Any amount paid under the Scheme shall be deposited under the Treasury Head of the relevant Act for which the scheme is being opted for.

(4) The applicant shall make a separate application for each assessment year under each relevant Act in Form **OTS-1** for which he intends to settle his outstanding dues.

Example:- Mr. X is in receipt of a demand which contains liability for the Haryana Value Added Tax Act and the Central Sales Tax Act also for the Financial Year 2013-14. In this case, if Mr. X wishes to settle his dues, he shall make separate application under the Haryana Value Added Tax Act and the Central Sales Tax Act for Financial Year 2013-14. Both his applications shall be considered as unique and shall be processed accordingly.

Settlement of outstanding dues

4. (1) An applicant opting for settlement of outstanding dues under this scheme shall have to pay, by way of settlement, an amount in lieu of his outstanding dues as mentioned in Schedule-I.

(2) The applicant may opt to make payment for settlement of his outstanding dues in lumpsum or in installments as per the option available in Schedule-II.

(3) The applicant may make the payment for the second installment by the last date of the third installment on payment of additional interest of eighteen percent per annum for the period of delay.

(4) If payment is not made within the period specified in Schedule-II or such period as provided in sub-clause (3) above, the provisional order of acceptance shall be deemed to be withdrawn and it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant and the jurisdictional authority shall issue the order of rejection in FORM OTS-5 accordingly.

Application procedure

5. (1) The applicant may opt for the scheme within ninety days from the appointed day.

(2) The applicant shall apply online in FORM OTS-1 along with proof of payment of the settlement amount or the first installment, whichever is applicable.

(3) On receipt of FORM OTS-1, a system generated acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM OTS-2.

Verification of form and extension of time limit

6. The procedure for processing of applications shall be in the following manner, namely:-

(a) The jurisdictional authority shall examine **FORM OTS-1** within thirty days from the date of acknowledgement and send the application along with his comments for the recommendations to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (hereinafter referred as "DETC") concerned.

(b) In case the jurisdictional authority has reasons to believe that a particular application does not pertain to his ward, then he may transfer such application to DETC. The DETC shall then transfer such application to the concerned jurisdictional authority for processing of the application. In such cases, the timeline specified in para (a) above shall be from the date of such transfer of application.

(c) The DETC shall further examine the application within fifteen days and send the case back to the jurisdictional authority for either issuing deficiency notice in **FORM OTS 3** or provisional settlement order in **FORM OTS 4A** (where the applicant has opted for installments or is supposed to submit proof of withdrawal of appeal) or a final order of settlement in **FORM OTS 4**.

(d) On receipt of communication from the DETC, the jurisdictional authority shall issue within fifteen days a deficiency notice in **FORM OTS 3** or provisional settlement order in **FORM OTS 4A** or a final order of settlement in **FORM OTS 4**, as the case may be.

(e) The applicant shall submit his reply in **FORM OTS-3A** electronically within fifteen days of the date of issuance of deficiency notice in **FORM OTS-3** along with requisite documents or proof of payment as required.

(f) On receipt of the reply of the applicant in **FORM OTS-3A**, the jurisdictional authority shall examine and send the case to the DETC with his recommendations within fifteen days from the date of **FORM OTS-3A**. The DETC shall examine the case within fifteen days and direct the jurisdictional authority either to issue provisional settlement order in **FORM OTS 4A** or a final order of settlement in **FORM OTS 4** or an order of rejection in **FORM OTS-5**.

(g) On receipt of the directions issued by the DETC, the jurisdictional authority, shall within fifteen days from the receipt of such communication issue a provisional settlement order in **FORM OTS 4A** or a final order of settlement in **FORM OTS 4** or an order of rejection in **FORM OTS-5**.

- (h) Any applicant interested to opt for the scheme shall withdraw the appeal, if any, pending before the appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court in respect of any statutory order, fully and un-conditionally and submit proof of such withdrawal of appeal in **FORM OTS-6** within one hundred eighty days from the receipt of **FORM OTS 4A** electronically to the jurisdictional authority before the final order of settlement.
- (i) In case **FORM OTS-6** is not furnished within one hundred eighty days from the receipt of **FORM OTS 4A**, it shall be presumed as if the application was never made and pending proceedings under the applicable relevant Act shall continue against the applicant.
- (j) Any proceeding pending before any appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court shall be kept in abeyance till the final order of settlement in **FORM OTS-4** or order of rejection in **FORM OTS-5** is passed under this scheme, for those applicants who are opting this scheme.
- (k) Where order of rejection of settlement in **FORM OTS-5** is issued, the amount paid, if any, by the applicant shall be adjusted against his liabilities under the relevant Act and such amount shall not be refunded in any case.

7. (1) The applicants whose outstanding dues have been uploaded by the jurisdictional authority in **FORM GST DRC-07A** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for recovery of such dues under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) shall also be eligible to take the benefit of the scheme.

(2) The jurisdictional authority shall after successful issuance of **FORM OTS-4** modify the demand created through **FORM GST DRC-07A** and issue **FORM GST DRC 08A** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017.

8. (1) The final order of settlement passed under this scheme with respect to the amount payable under this scheme shall be conclusive as to the matter and time stated therein and the applicant shall not be liable, -

- (a) to pay any further tax, interest or penalty with respect to the matter and time period covered in the final order of settlement;
- (b) to be prosecuted under the relevant Act with respect to the matter and time period covered in the order;

(2) All matters and time period covered by such order shall not be re-opened in any other proceedings under the relevant Act:

Provided that in case where any material particular furnished in the application is subsequently found to be false, within a period of two years from the date of order of settlement, it shall be presumed as if the application was never made and proceedings under the applicable relevant Act shall be instituted against the applicant.

9. Any amount of tax, interest or penalty or any other sum payable or paid before the appointed day shall not be refunded or adjusted under this scheme.

10. The authority who has passed the final order under this scheme, may rectify any error which is apparent on the face of record in such order, either on his own motion or where such error is brought to his notice by the affected person within a period of 30 days from the date of issuance of such order.

11. If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty.

12. In case of any doubt arising out of this scheme, the decision of the Excise and Taxation Commissioner, Haryana thereon shall be final.

13. The following applicants shall not be eligible to opt for the scheme in case,-

- (a) criminal proceedings have been initiated against the applicant for any reason(s) under the relevant Acts;
- (b) the demand relates to erroneous refund(s) under the relevant Act.

Provisions under Section 142 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 for recovery of outstanding dues of existing law.

Privileges emanating from the final order of settlement.

No refund of amount already paid as tax, interest or penalty.
Rectification of errors.

Removal of difficulty.

Removal of doubt.

Applicants not eligible to opt scheme.

Restrictions with regard to settlement.

14. Any amount paid under this scheme shall neither be paid through Input tax nor shall be allowed to be claimed as Input tax by any person under the relevant Act or any other Act.

No Appeal against the final order of settlement.

15. No appeal shall lie before any appellate authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court against the final orders passed by the jurisdictional authority under this scheme.

Extension of time period.

16. (1) The Government, either on its own motion or on representation from stake holders may extend the time period for applying to this scheme.

(2) The Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) on case to case basis may extend time period for issuance of any notice or order or any recommendations issued under this scheme by the DETC or the jurisdictional authority for a further period of not more than thirty days for reasons to be recorded in writing.

Indemnity.

17. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any official /officer of the Government for anything which is done or intended to be done in good faith, in pursuance of this scheme.

(2) No proceeding shall be commenced against any official /officer merely on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of outstanding dues payable by the applicant, unless there is evidence of misconduct.

Schedule –I: Settlement amount to be paid in lieu of outstanding dues*[see clause 4(1)].*

1	2	3	4	5
Serial Number	Category	Percentage of Tax or any other amount payable	Percentage of interest associated with tax or any other sum payable as per column (3)	Percentage of penalty associated with tax or any other sum payable as per column (3)
1.	Admitted Tax	• 100%	• 0%	• 0%
2.	Disputed Tax	• 30% in case of tax amount equal to or less than Rs. 50 lacs • 50% in all other cases	• 0%	• 0%
3.	Undisputed Tax	• 40% in case of tax amount less than or equal to Rs. 50 lacs. • 60% in all other cases	• 0%	• 0%
4.	Differential Tax	• 30%	• 0%	• 0%

Schedule-II: Option to pay in installments

1	2	3	4	5
Serial Number	Settlement Amount of tax (Refer Column (3) of Schedule-I) (in Rs.)	Amount to be paid at the time of application	2nd Installment (within 90 days from the date of provisional order of settlement)	3rd Installment (within 180 days from the date of provisional order of settlement)
1.	Upto 10 Lakhs	Full and final settlement amount to be paid alongwith FORM OTS-1 .	Nil	Nil
2.	10 Lakhs to 25 Lakhs	50% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1 .	Balance 50% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1 A .	Nil
3.	More than 25 Lakhs	40% of the settlement amount alongwith FORM OTS-1 .	30% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1A .	Balance 30% of the settlement amount alongwith intimation in FORM OTS-1B

Form OTS-1 <i>(see clause 3, 5 and 6)</i>		
APPLICATION FORM FOR OPTING THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2023		
<<System Generated Unique Number and Date>>		
S.No.	Particulars	
1	(a) Name of the Applicant (Please see the definition of applicant)	<< mandatory>>
	(b) Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)	<< mandatory>>
	(c) PAN	<< Upload Option>>+ comment box <<mandatory field>>
	(d) Mobile	<< mandatory>>
	(e) E-mail id	<< mandatory>>
	(f) SCO/Booth/Shop/Building/Flat/Floor No.	<< mandatory>>
	(g) Sector/Area	<< mandatory>>
	(h) City/Town/Village	<< mandatory>>
	(i) District	<< Drop Down >><< mandatory>>
	(j) Pin Code	<< mandatory>>
	(k) State	Haryana
	(l) Jurisdictional District	<< Drop Down >>
	(m) Jurisdictional Ward	<< Drop Down >>
	2	(a) Name of the Authorized signatory **
(b) Email id of the authorized signatory		<< mandatory>>
(c) Mobile no. of the authorized signatory		<< mandatory>>
(d) Any ID Proof of the authorized signatory (PAN/Aadhar Card/ Driving License/ Voter ID Card/Passport/PPP or any other Government issued ID card)		<< upload option>> + comment box << mandatory>>
3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.	Relevant Act<< Drop Down >> Assessment Year << Drop Down>> (only one option can be chosen)
4	Whether any cases are pending before any appellate authority under the relevant Act, High Court, or Supreme Court.	Yes <input checked="" type="checkbox"/> If Yes is selected then following comment boxes should open: 1. Case Number <input type="text"/> 2. Pending before Authority <input type="text"/> 3. Date of filling Appeal/ case <input type="text"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <<mandatory field>>

5	Whether criminal proceedings have been initiated against the applicant for any reason(s) under the relevant Act;	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> << if yes selected, OTS 1 cannot be generated>>
6	Whether the demand relates to erroneous refund(s) under the Relevant Act	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> << if yes selected, OTS 1 cannot be generated>>
7	Details of settlement of outstanding dues as per Schedule-I	

Sr. No.	Name of the relevant Act <<auto populated>>	Assessment year <<auto populated>>	Order No. vide which outstanding dues were quantified<< mandatory>>	Date of order<< mandatory>>	Total amount involved in order stated in column no (4) << mandatory>>	Choose 1. Admitted Tax 2. Disputed tax 3. Undisputed tax 4. Differential Tax << Drop down>> (multiple options) << mandatory>>	Amount of tax involved or any other amount payable in column no (7) << mandatory>>	Settlement amount in lieu of (8) as per column (3) of schedule I (Auto-populated)	Total amount of interest involved << mandatory>>	Settlement amount in lieu of (10) as per column (4) of schedule I (Auto-populated)	Total amount of penalty involved << mandatory>>	Settlement amount in lieu of (12) as per as per column (5) schedule I (Auto-populated)	Net Amount Payable (9+11+13)<< mandatory>>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total													

8	Total settlement amount as per 7(14)						Auto populated figure of total of 7(14)	
9	Category of Settlement of dues as per 7(9)						<10 lacs, 10-25 lacs, >25 lacs <<auto populated>>	
10	Whether Installment Facility opted						Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> (if dues in S.No. 9 is <10 lacs)	
11	Installment Schedule							
	S.No.	Total settlement amount	Amount of 1 st installment	Date of 1 st installment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment	Date of 3 rd installment
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1							
12	Details of Payments made.							
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN		Serial number of CIN		Date of CIN	Amount (in Rs.)
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
	1							
	2							
	<input type="checkbox"/> I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.						Total	

13	Documents to be uploaded	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanent Account Number 2. Assessment order vide which dues were quantified 3. Proof of pending appeals, if any 4. Proof of payment 5. Any other document
14	<p>Declaration:</p> <p>I herein above declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof.</p> <p>I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.</p> <p>Place: _____ Date: <>auto generated<>(editable)</p> <p>Note: -All the amount to be paid in Rs.</p>	

**

Constitution of Business	Person who can be authorized to file the application of OTS
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing/Authorized Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing/Whole-time Directors
Society/Club/Trust/AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing/Whole-time Directors
Unlimited Company	Managing/Whole-time Directors
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorized Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorized Person in India
Others (specify)	Person in charge

Form OTS-1A

(see schedule II)

INTIMATION FOR SECOND INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2023

<<System Generated Unique Number and Date>>

S.No.	Particulars								
1	(a)	Name of the Applicant		<< auto populated>>					
	(b)	Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention ‘unregistered’ if not registered)		<< auto populated>>					
	(c)	System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -1		Input Box<< auto populated>>					
	(d)	System Generated Unique Number & Date of FORM OTS -4A		<< auto populated>>					
	(e)	Jurisdictional District		<< auto populated>>					
	(f)	Jurisdictional Ward		<< auto populated>>					
2	(a)	Name of the Authorized signatory		<< auto populated>>					
	(b)	Email id of the authorized signatory		<< auto populated>>					
	(c)	Mobile no. of the authorized signatory		<< auto populated>>					
3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.		Relevant Act<<auto populated>> Assessment Year <<auto populated>>						
4	Total settlement amount as per S.No. 8 of FORM OTS-1					<<Auto populated>>			
5.	Total settlement amount as per FORM OTS-4A								
6	Installment Schedule << auto populated from FORM OTS 4A >>								
	S.No.	Total settlement amount	Amount of 1 st installment	Date of 1 st installment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment	Date of 3 rd installment	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	1								
7	Installment amount to be paid as per 6(5) above								
8	Interest paid on delayed payment of installment @ 18% p.a, if any								
9	Details of Payments made.								
	Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN		Date of CIN	Amount (in Rs.)		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
	1								
	2								
	<input checked="" type="checkbox"/> I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.					Total			

10	Documents to be uploaded	1. Proof of payment 2. Any other document
11	<p>Declaration:</p> <p>I herein above declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof.</p> <p>I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.</p> <p>Place: _____</p> <p>Date: <>auto generated<>(editable)</p> <p>Note: -All the amount to be paid in Rs.</p>	

Form OTS-1B <i>(see schedule II)</i>									
INTIMATION FOR THIRD INSTALLMENT UNDER THE HARYANA ONE TIME SETTLEMENT SCHEME FOR RECOVERY OF OUTSTANDING DUES, 2023									
<<System Generated Unique Number and Date>>									
S.No.	Particulars								
1	(a)	Name of the Applicant			<< auto populated>>				
	(b)	Registration No. under the relevant Act (if registered) (Please mention 'unregistered' if not registered)			<< auto populated>>				
	(c)	System Generated Unique Number & Date of Form OTS -1			Input Box<< auto populated>>				
	(d)	System Generated Unique Number & Date of Form OTS -1A			Input Box<< auto populated>>				
	(e)	System Generated Unique Number & Date of Form OTS -4A			Input Box<< auto populated>>				
	(f)	Jurisdictional District			<< auto populated>>				
	(g)	Jurisdictional Ward			<< auto populated>>				
2	(a)	Name of the Authorized signatory			<< auto populated>>				
	(b)	Email id of the authorized signatory			<< auto populated>>				
	(c)	Mobile no. of the authorized signatory			<< auto populated>>				
3	Name of the relevant Act and period for which this application is submitted.			Relevant Act<<auto populated>> Assessment Year <<auto populated>>					
4	Total settlement amount as per S.No. 8 of FORM OTS-1					<<Auto populated>>			
5	Total settlement amount as per FORM OTS 4-A								
6	Installment Schedule << auto populated from FORM OTS 4A >>								
	S.No.	Total settlement amount	Amount of 1 st installment	Date of 1 st installment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment	Date of 3 rd installment	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	1								
	7	Installment amount to be paid as per 6(7) above.							
8	Details of Payments made.								
Sr. No	Serial number of the GRN	Date of the GRN	CIN			Date of CIN	Amount (in Rs.)		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
1									
2									
<input checked="" type="checkbox"/> I agree that GRN details furnished above have been checked and not previously used anywhere.						Total			

9	Documents to be uploaded	1. Proof of payment 2. Any other document
10	<p>Declaration:</p> <p>I herein above declare that the information and declarations stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and that nothing has been concealed therein. The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 has been opted after fully understanding its terms and conditions thereof.</p> <p>I also affirm that I will discharge the settlement amount as applicable to me. I further affirm that in case of failure to pay any pending amount, any payment made under the Scheme shall be adjusted against my liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.</p> <p style="text-align: right;">(Name of the applicant) <<auto</p> <p>Place: _____ generated>>(editable)</p> <p>Date: <<auto generated>></p> <p>Note: -All the amount to be paid in Rs.</p>	

FORM OTS-2*(see clause 5(3))***Acknowledgement of Application in Form OTS-1**

Your application in Form OTS-1, reference no. _____ dated _____ for settlement of outstanding dues, pertaining to _____ (Name of the Relevant Act), under the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 for the assessment year _____ is hereby acknowledged.

Excise and Taxation Department

Government of Haryana

** This is a system generated acknowledgement and does not require any signature **

FORM OTS-3*(see clause 6)***Deficiency Notice**

To

Name of the applicant<< auto populated >>**Address of the applicant**<< auto populated >>**TIN/RC No. (if applicable)**<< auto populated >>**OTS 3 Reference No.**<< system generated>>**Dated**<<system generated>>**Subject: -** **Deficiency Notice.****Reference: -** **FORM OTS 1 Reference No.**<<auto populated>>**Dated**<<auto populated>>

Whereas you have made an application under The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023. Upon examination of your application, the following deficiencies have been observed in **Form OTS-1** bearing reference No._____ dated_____:

- (i)
- (ii)
- (iii)

<< **Upload option**>>

Your reply to this notice must reach the undersigned in FORM OTS-3A alongwith proof of payment (if any) within fifteen days of receipt of this notice. In case of failure to comply with the terms of this notice, your application will be rejected without further notice and the payment made under the Scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act and shall not be refunded in any case.

Excise and Taxation Officer
District_____
Ward_____

FORM OTS 3A

(see clause 6)

Reply to Deficiency Notice

To

The Excise & Taxation Officer,**District<<Drop Down>>****Ward<< Drop Down>>****Name of the applicant<< auto populated>>****Address of the applicant<< auto populated>>****Details of FORM OTS 3 Notice No.<< auto populated>>**Dated**<< auto populated>>****TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>****Subject: - Reply to Deficiency Notice in FORM OTS 3.****Reference: - FORM OTS 3 Reference No.<< auto populated>>**Dated**<< auto populated>>**

This is with reference to the deficiency notice issued in **FORM OTS 3** vide no.<< auto populated>> dated << auto populated>> from your office. The point wise reply to the deficiencies raised is as under:

- (a)
- (b)
- (c)

Detail of Payment made					
Sr. No.	Serial number of the GRN	Date of the GRN	Serial number of CIN	Date of CIN	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
Total					
Documents to be uploaded				1. Proof of payment 2. Any other document	

Place: _____
 Date: <<auto generated>>

(Name of the applicant)
 <<auto generated>>(editable)

Note: -All the amount to be paid in Rs.

FORM OTS-4A
(see clause 6)
Order of Provisional Settlement

To

Name of the applicant<<auto populated>>
Address of the applicant<<auto populated>>
TIN/RC No. (if applicable)<<auto populated>>
Order No.<< system generated>> **Dated**<< system generated>>

Subject: - Provisional Order of Settlement.**Reference: - FORM OTS 1 Reference No.<<auto populated>> **Dated**<<auto populated>>**

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023. On examination, your application has been found to be in order. Accordingly, the order of provisional settlement is, hereby, passed as follows:

Name of the Relevant Act<<auto populated/editable>>**Assessment Year**<< auto populated/ editable>>**Table-I**

Details of settlement of outstanding dues as per Schedule-I
<<Auto populated and editable table of dues as per FORM OTS 1 S.No. 7>>

Sr. No.	Name of the relevant Act	Assessment year	Order No. vide which outstanding dues were quantified	Date of order	Total amount involved in order stated in column no. (4)	1. Admitted Tax 2. Disputed tax 3. Undisputed tax 4. Differential Tax	Amount of tax involved or any other amount payable in column no. (7)	Settlement amount in lieu of (8) as per column (3) of schedule I	Total amount of interest involved	Settlement amount in lieu of (10) as per column (4) of schedule I	Total amount of penalty involved	Settlement amount in lieu of (12) as per column (5) schedule I	Net Amount Payable (9+11+13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(i)													
(ii)													
(iii)													
(iv)													
Total													

Table-II

Installment Schedule << auto populated but editable>>

S. No.	Total settlement amount	Amount of 1 st installment	Date of 1 st installment	Amount of 2 nd Installment	Date of 2 nd installment	Amount of 3 rd installment	Date of 3 rd installment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							

Table-III

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
(i)	Settlement amount payable as per Table-I	
(ii)	Less: Amount paid by the applicant	
(iii)	Balance (1-2)	

This is a provisional order and the final order of settlement in **FORM OTS 4** shall only be passed after full payment and submission of proof of withdrawal of pending appeals in **FORM OTS 6**, if applicable by the applicant.

Excise and Taxation Officer
 District _____
 Ward _____

FORM OTS-4

(see clause 6 and 7)

Final Order of Settlement

To

Name of the applicant<< auto populated>>**Address of the applicant**<< auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)**<< auto populated>>**Order No.**<< system generated>>**Dated**<< system generated>>**Subject:** - **Final Order of Settlement.****Reference:** - **FORM OTS 1 Reference No.**<< auto populated>>**Dated**<< auto populated>>

Whereas, you have opted for The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023. Your application has been examined in detail, accordingly the final order of settlement is hereby passed as under:

Name of the Relevant Act<< auto populated/ editable>>**Assessment Year**<< auto populated/ editable>>**Table-I**

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Settlement Amount payable as per FORM OTS-1/OTS-4A	
2.	Less: - a) Amount paid by the applicant in FORM OTS 1 (1 st installment) b) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1A (2 nd installment) * c) Amount paid by the applicant in intimation FORM OTS 1B (3 rd installment)	
3.	Interest paid in lieu of delayed payment in second installment	
4.	Balance (1-2)	<<It should be zero>>

* Interest if any, on delayed installment shall not be mentioned in this column.

The appeals pending if any, before any Appellate Authority under the relevant Act, High Court or Supreme Court have been withdrawn and proof of such withdrawal of appeal has been submitted in **FORM OTS-6**, bearing number <>auto populated<>dated<>auto populated<>.

On perusal of your application, payments made, and all other documents in consideration, I find that your following outstanding dues have been settled through The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023.

Table-II

Sr. No.	Relevant Act	Assessment Year	Settlement Amount
(a)	(b)	(c)	(d)
1.			
2.			
Total			

Excise and Taxation Officer
 District _____
 Ward _____

FORM OTS-5*(see clause 4)***Order of Rejection**

To

Name of the applicant << auto populated>>**Address of the applicant**<< auto populated>>**TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>****Order No.**<< system generated>>**Dated**<< system generated>>**Subject: - Order of Rejection.****Reference: - FORM OTS 1 reference No.** << auto populated>>**dated**<< auto populated>>**FORM OTS-3 No., if applicable**<< auto populated>>**dated**<< auto populated>>

Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2023 vide **FORM OTS -1** bearing reference no.<< auto populated>> dated<< auto populated>>. Your application was examined and was not found in order and the following reasons have been recorded to reject your application in **FORM OTS 1**: -

(a)

(b)

(c)

<<upload option>>

Further, it is intimated that the amount paid under the scheme shall be adjusted against your liabilities under the Relevant Act.

Excise and Taxation Officer

District_____

Ward_____

FORM OTS 6

(see clause 6)

**Intimation regarding withdrawal of pending Appeal before any Appellate Authority under the relevant Act,
High Court or Supreme Court**

<<system generated reference number>>

To

The Excise & Taxation Officer,**District < Drop Down>****Ward < Drop Down>****Name of the applicant<< auto populated>>****Address of the applicant<< auto populated>>****Details of FORM OTS 1 Reference No.<< auto populated>>**Dated**<< auto populated>>****TIN/RC No. (if applicable)<< auto populated>>****Subject: - Withdrawal of Appeal pending before any Appellate Authority under the relevant Act,
High Court or Supreme Court.****Reference: - FORM OTS 1 Reference No. << auto populated>>**Dated**<< auto populated>>**

In compliance of my declaration in **FORM OTS-1** bearing reference number <<auto populated>>dated<<auto populated>> and your order in **FORM OTS 4A** bearing number<< auto populated>> dated <<auto populated>>, I (name of the applicant) <<auto populated>> have withdrawn the appeal pending before the _____ (mention the name of the Authority) against the assessment order for the assessment year <<auto populated>>under the <<auto populated>>Act. The proof of such withdrawal is annexed herewith.

<< upload option>>

I understand that final order of settlement in **FORM OTS 4** shall only be passed by the jurisdictional authority on acceptance of such proof of withdrawal.

(Name of the applicant)

<<auto generated>>(editable)

Place: _____

Date: <<auto generated>>

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.